HINDUSTAN TIMES, Delhi, 5.3.2025
Page No. 22, Size:(9.58)cms X (14.13)cms.

NHRC and MEA organise Capacity Building Programme

The National Human Rights Commission (NHRC), India with the Union Ministry of External Affairs (MEA) is organising a six-day ITEC Executive Capacity Building Programme on human rights for senior-level functionaries of the NHRIs of Global South at New Delhi from March 3 to 8. 47 participants from the NHRIs of 14 countries of Global South are likely to attend it. These are Madagascar, Uganda, Samoa, Timor Letse, DR Congo, Togo, Mali, Nigeria, Egypt, Tanzania, Mauritius, Burundi, Turkmenistan and Qatar.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 5.3.2025
Page No. 22, Size:(9.83)cms X (16.02)cms.

NHRC announces winners of short films competition

NHRC, India announced the winners of its 10th prestigious annual competition for short films on human rights in 2024. It has chosen 'Doodh Ganga- Valley's Dying Lifeline' for the first prize of Rs 2 lakh. The documentary film by Er Abdul Rashid Bhat from Jammu & Kashmir raises concerns on how the free flow of various waste into the pristine water of Doodh Ganga river has polluted it and the need for its restoration for the overall good of the people in the valley. The film is in English, Hindi and Urdu with subtitles presented in English.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NAVBHARAT TIMES, Delhi, 5.3.2025
Page No. 18, Size:(2.13)cms X (6.11)cms.

ओडिशा में नेपाली छात्र की मौत की जांच के आदेश

■ **भाषा, भुवनेश्वर:** नैशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन (NHRC) ने ओडिशा के KIIT यूनिवर्सिटी में एक नेपाली छात्रा की मौत की मौके पर जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने अपने अधिकारियों से 10 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा है।

NHRC ने यह आदेश एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जारी किया, जिसमें कहा गया था कि 20 वर्षीय प्रकृति लामसाल ने 16 फरवरी को अपने हॉस्टल के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आयोग ने कहा कि जांच मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। NHRC ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग रजिस्ट्रार (विधि) को निर्देश देता है कि वह भुवनेश्वर स्थित KIIT यूनिवर्सिटी में जांच मौके पर करें और छानबीन दल में जांच प्रभाग के दो अधिकारी हों। जिनमें से एक एसएसपी के पद से नीचे का न हो और दूसरा विधि प्रभाग का एक अधिकारी/कर्मचारी हो। आयोग ने इन्हें 10 मार्च 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

DAINIK JAGRAN (JAGRAN CITY), Ghaziabad, 5.3.2025
Page No. 2, Size:(8.88)cms X (12.14)cms.

तीन कामगारों की मौत मामले में एनएचआरसी ने मांगा जवाब

राजनगर एक्सटेंशन में बीते महीने निर्माणाधीन साइटों पर हुए हादसों में तीन कामगारों की मौत हो गई थी, की गई थी शिकायत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : राजनगर एक्सटेंशन में फरवरी में चार दिन में तीन कामगारों की निर्माणाधीन साइट पर हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से जवाब तलब किया है। शिकायतकर्ता राजीव कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तीनों मामलों में गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया। पुलिस ने शिकायत न मिलने पर खुद संज्ञान लेकर लापरवाही या गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज नहीं किया। एनएचआरसी ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को साहिबाबाद निवासी राजीव कुमार शर्मा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद पुलिस से फरवरी माह में राजनगर एक्सटेंशन में हुई तीन कामगारों की मौत के मामले में जांच करवा कर 15 दिन में जांच रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। राजीव शर्मा के मुताबिक तीनों ही मामलों में स्थानीय पुलिस ने बिल्डरों और ठेकेदारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के बजाय यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था कि मृतकों के स्वजन ने लिखित शिकायत नहीं दी है। नियमानुसार अगर मृतकों के स्वजन की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी तब भी पुलिस को घटना पर स्वयं संज्ञान लेकर घटना के जिम्मेदार बिल्डरों व ठेकेदारों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। नाबालिग की मौत में श्रम कानून के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए था।

AMAR UJALA, Delhi, 5.3.2025
Page No. 14, Size:(3.25)cms X (3.40)cms.

मानवाधिकार आयोग ने दिए नेपाली छात्रा की मौत की जांच के आदेश

भुवनेश्वर। मानवाधिकार आयोग ने केआईआईटी विवि में 20 वर्षीय नेपाली छात्रा की रहस्यमय मौत के मामले में जांच का आदेश दिया। आयोग ने 10 मार्च तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कंप्यूटर साइंस की तृतीय वर्ष की छात्रा प्रकृति 16 फरवरी को अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई थी। पुलिस ने आत्महत्या का संदेह जताया है, लेकिन परिजनों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इस संबंध में इंजीनियरिंग छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया। एजेंसी

PIB

NHRC, India begins its two-week Online Short Term Internship Programme

NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal, in his inaugural address says, transformation lies not merely in observing injustices but in taking decisive action

Says, cultivating responsiveness to rights violations, from subtle indignities to overt abuses, is paramount

80 university-level students from diverse academic disciplines from 18 States and Union Territories of the country, shortlisted to attend out of 932 applicants

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2108124

Posted On: 04 MAR 2025 5:34PM by PIB Delhi

The National Human Rights Commission (NHRC), India began its two-week online short term internship (OSTI). 80 university-level students from diverse academic disciplines from 18 States and Union Territories of the country have been shortlisted out of 932 applicants to participate in this programme. The two-week programme aims to foster human rights consciousness and proactive engagement, empowering individuals to serve as catalysts for a more just, equitable, and humane society for all citizens.

NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal in his address urged the students to view this period not merely as an addition to their curriculum vitae, but as a critical phase in their personal and professional development. He emphasised that the true value of the internship lies in the deep, lasting knowledge offered for the transformation of the interns' thinking, behaviour, and sensitivity to the challenges confronting society. In an era when information is readily accessible on laptops and mobile devices, the real challenge is bridging the gap between digital access and internalisation followed by application.

The Secretary General stressed that the two-week programme is designed to foster sensitivity to suffering and injustice, along with instilling a deep sense of responsibility. He noted that true transformation lies not merely in observing injustices but in taking decisive action, and that cultivating responsiveness to rights violations—from subtle indignities to overt abuses—is paramount. This programme aspires to instill these qualities, ensuring that education transcends mere knowledge to cultivate a more humane and engaged individual.

Lt Col Virender Singh, Director, NHRC, India gave an overview of the internship programme and meticulously designed curriculum. The curriculum includes lectures, team and individual competitions such as group research project presentation, book review and declamation competition and virtual tours of institutions such as Tihar Jail, which offer first-hand insights into human rights realities.

The OSTI is designed to equip students from diverse academic backgrounds with the knowledge and skills necessary to address human rights challenges. Through interactive sessions and engaging activities, interns will gain a deeper understanding of international human rights law, human rights issues specific to India, and effective advocacy strategies.

*****

NSK

(Release ID: 2108124) Visitor Counter : 419

PIB

एनएचआरसी, भारत ने अपना दो सप्ताह का ऑनलाइन लघु अवधि इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया

एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि परिवर्तन केवल अन्याय को देखने में नहीं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई करने में निहित है

उन्होंने कहा कि सूक्ष्म अपमान से लेकर प्रत्यक्ष दुर्व्यवहार तक, अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है

देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विभिन्न शैक्षणिक विषयों के 80 विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को 932 आवेदकों में से भाग लेने के लिए चुना गया

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2108201

Posted On: 04 MAR 2025 5:34PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने अपनी दो सप्ताह की ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) शुरू की। देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न शैक्षणिक विषयों के 80 विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 932 आवेदकों में से चुना गया है। दो सप्ताह के इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानवाधिकार चेतना और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, व्यक्तियों को सभी नागरिकों के लिए अधिक न्यायसंगत, समतापूर्ण और मानवीय समाज के लिए उत्प्रेरक के रूप में सेवा करने के लिए सशक्त बनाना है।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने अपने संबोधन में छात्रों से आग्रह किया कि वे इस अवधि को वे केवल अपने जीवन परिचय में एक और जोड़ के रूप में न देखकर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंटर्नशिप का वास्तविक मूल्य समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति इंटर्न की सोच, व्यवहार और संवेदनशीलता को बदलने के लिए दिए जाने वाले गहन, स्थायी ज्ञान में निहित है। ऐसे युग में जब लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों पर जानकारी आसानी से उपलब्ध है, असली चुनौती डिजिटल पहुंच और प्रयोग के बाद उसे अपनाने के बीच की खाई को पाटना है।

महासचिव ने जोर देकर कहा कि दो सप्ताह का कार्यक्रम पीड़ा और अन्याय के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के साथ-साथ जिम्मेदारी की गहरी भावना पैदा करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सच्चा परिवर्तन केवल अन्याय को पहचानने में नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई करने में निहित है, और अधिकारों के उल्लंघन के प्रति, सूक्ष्म अपमान से लेकर खुले तौर पर दुर्व्यवहार तक, संवेदनशीलता विकसित करना सर्वोपरि है। यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षा केवल ज्ञान से आगे बढ़कर एक अधिक मानवीय और प्रतिबद्ध व्यक्ति का निर्माण करती है, इस कार्यक्रम से इन गुणों को विकसित करने की आशा है।

एनएचआरसी, भारत के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने इंटर्नशिप कार्यक्रम और सावधानीपूर्वक तैयार किए गए पाठ्यक्रम का अवलोकन दिया।

पाठ्यक्रम में व्याख्यान, टीम और व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं जैसे समूह अनुसंधान परियोजना प्रस्तुति, पुस्तक समीक्षा और भाषण प्रतियोगिता और तिहाड़ जेल जैसे संस्थानों के आभासी दौरे शामिल हैं, जो मानवाधिकार वास्तविकताओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं।

ओएसटीआई को विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों को मानवाधिकार चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंटरेक्टिव सत्रों और आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से, प्रशिक्षुओं को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, भारत के विशिष्ट मानवाधिकार मुद्दों और प्रभावी वकालत रणनीतियों की गहरी समझ हासिल होगी।

***

एमजी/आरपीएम/केसी/पीएस/डीए

(Release ID: 2108201) Visitor Counter : 45

Devdiscourse

NHRC India Launches Online Internship to Cultivate Human Rights Awareness and Advocacy

Shri Bharat Lal highlighted that the essence of this programme lies in developing a deep sensitivity to suffering and injustice, instilling a profound sense of responsibility among participants.

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3285203-enhancing-earths-safety-a-journey-in-earthquake-risk-reduction

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 04-03-2025 21:37 IST | Created: 04-03-2025 21:37 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) of India has commenced its two-week Online Short-Term Internship (OSTI), aimed at fostering human rights awareness and proactive engagement among university students across the country. Out of a competitive pool of 932 applicants, 80 students from diverse academic disciplines, representing 18 states and union territories, have been selected to participate in this prestigious programme.

The internship seeks to empower young individuals to become catalysts for a more just, equitable, and humane society. NHRC Secretary General, Shri Bharat Lal, emphasized in his address that the internship is more than just a credential for students' résumés; it is a transformative experience meant to shape their perspectives, behavior, and sensitivity toward societal challenges. He underscored the importance of bridging the gap between digital access to information and its internalization, followed by practical application.

Shri Bharat Lal highlighted that the essence of this programme lies in developing a deep sensitivity to suffering and injustice, instilling a profound sense of responsibility among participants. He pointed out that true transformation occurs not merely by recognizing injustices but by taking decisive action against them. The internship is designed to cultivate responsiveness to human rights violations, ranging from subtle indignities to outright abuses, ensuring that education evolves beyond theoretical knowledge to create engaged and humane individuals.

Providing an overview of the meticulously structured programme, NHRC, India Director, Lt Col Virender Singh, outlined its dynamic curriculum. The internship encompasses a series of lectures, team-based and individual competitions—including group research project presentations, book reviews, and declamation contests—and virtual visits to significant institutions like Tihar Jail. These experiences offer students firsthand insights into the realities of human rights concerns in India.

The OSTI is structured to equip students with the necessary knowledge and skills to effectively address human rights challenges. Through interactive sessions and engaging activities, interns will gain a deeper understanding of international human rights laws,

human rights issues specific to India, and effective advocacy strategies. By the end of the programme, participants will not only have enhanced their knowledge but also developed the moral and intellectual framework required to champion human rights in their respective fields.

India Ground Report

New Delhi : एनएचआरसी ने दो सप्ताह का ऑनलाइन लघु अवधि इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया

https://indiagroundreport.com/new-delhi-nhrc-launches-two-week-online-short-term-internship-programme/

By India Ground Report | March 4, 2025

नई दिल्ली :(New Delhi) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने अपनी दो सप्ताह की ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) शुरू की। देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न शैक्षणिक विषयों के 80 विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 932 आवेदकों में से चुना गया है। दो सप्ताह के इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानवाधिकार चेतना और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, व्यक्तियों को सभी नागरिकों के लिए अधिक न्यायसंगत, समतापूर्ण और मानवीय समाज के लिए उत्प्रेरक के रूप में सेवा करने के लिए सशक्त बनाना है।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव भरत लाल ने अपने संबोधन में छात्रों से आग्रह किया कि वे इस अवधि को केवल अपने जीवन परिचय में एक और जोड़ के रूप में न देखकर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंटर्नशिप का वास्तविक मूल्य समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति इंटर्न की सोच, व्यवहार और संवेदनशीलता को बदलने के लिए दिए जाने वाले गहन, स्थायी ज्ञान में निहित है। ऐसे युग में जब लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों पर जानकारी आसानी से उपलब्ध है, असली चुनौती डिजिटल पहुंच और प्रयोग के बाद उसे अपनाने के बीच की खाई को पाटना है।

महासचिव ने जोर देकर कहा कि दो सप्ताह का कार्यक्रम पीड़ा और अन्याय के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के साथ-साथ जिम्मेदारी की गहरी भावना पैदा करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सच्चा परिवर्तन केवल अन्याय को पहचानने में नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई करने में निहित है।

Construction World

NHRC-MEA Launch Human Rights Training for Global South Officials in Delhi

https://www.constructionworld.in/policy-updates-and-economic-news/nhrc-mea-launch-human-rights-training-for-global-south-officials-in-delhi/69793

04 Mar 2025 2 Min Read CW Team

The six-day Indian Technical and Economic Cooperation Executive (ITEC) Capacity Building Programme on human rights for the NHRIs of Global South, being organized by the National Human Rights Commission (NHRC), India in partnership with the Union Ministry of External Affairs (MEA) began in New Delhi today. About 47 participants from the NHRIs of 14 countries of the Global South have confirmed their participation. These are Madagascar, Uganda, Samoa, Timor Leste, DR Congo, Togo, Mali, Nigeria, Egypt, Tanzania, Mauritius, Burundi, Turkmenistan, and Qatar.

Justice V Ramasubramanian, Chairperson, NHRC, India in his inaugural address said that India is a country of rich diverse cultural ethos with various castes, communities, art forms and languages and yet it thrives in its unity of shared values and traditions for centuries. However, he said that diversity also comes with diverse problems requiring diverse solutions. Every country has its socio-cultural, political, and economic traditions and diversities may face challenges while addressing the human rights issues given their standardised approaches set to dealing with them following the Universal Declaration of Human Rights. Therefore, solutions to the problems can’t be tailor-made for every country to follow.

Justice Ramasubramanian said that such platforms like ITEC provide an opportunity to share and exchange each other’s rich cultural diversity and human rights values to think and find ways how best to address the ever-emerging human rights challenges in each country with its social, cultural, political and economic realities.

He expressed his gratitude to the participating senior functionaries of the NHRIs of Global South and their countries for accepting NHRC, India’s invitation to depute them for participation. He also referred to many ancient Indian texts highlighting the human values and ethos practiced in the countries or centuries, which hold relevance even today for the whole world.

The Economic Times

Odisha: NHRC orders probe into Nepalese student''s death at KIIT, seeks report by Mar 10

https://economictimes.indiatimes.com/news/india/odisha-nhrc-orders-probe-into-nepalese-students-death-at-kiit-seeks-report-by-mar-10/articleshow/118705162.cms?from=mdr

PTI | Last Updated: Mar 04, 2025, 02:16:00 PM IST

Synopsis

The NHRC has initiated an on-spot inquiry into the death of Prakriti Lamsal, a Nepalese student at KIIT University, who allegedly died by suicide. She reportedly faced harassment by her ex-boyfriend and neglect by the university. Ten KIIT employees are accused of assaulting Nepalese students protesting for justice. The inquiry report is expected by March 10.

The National Human Rights Commission (NHRC) has ordered an on-spot inquiry into the death of a Nepalese girl student at KIIT University in Odisha and asked its officials to submit a report by March 10. The NHRC issued the order while acting on a complaint that 20-year-old Prakriti Lamsal died allegedly by suicide in her hostel room on February 16.

The commission said that the investigation should be held in accordance with the provisions of the Protection of Human Rights Act, 1993.

"Considering the seriousness of the matter, the commission directs the Registrar (Law) to proceed for an inquiry in KIIT University, Bhubaneswar to conduct an on-spot inquiry along with a team consisting of two officers from the investigation division, one not below the rank of SSP and one officer/official from Law Division, and submit its inquiry report to the Commission by 10th March, 2025," the NHRC order said.

Complainant Ashutosh B, in his petition, alleged that Lamsal, a Nepalese student at Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University, had faced harassment by her ex-boyfriend and that the university's International Relations Office (IRO) had neglected her complaints, leading to her tragic suicide.

The complainant also claimed that protests by Nepalese students, who sought justice in the incident, were met with verbal abuse, threats, and physical assault by KIIT officials and security guards.

The petitioner also urged the commission to take action against KIIT officials, including founder Achyuta Samanta, for their "failure to address harassment complaints and their involvement in the exploitation of tribal students".

Prakriti, a third-year Computer Science student at KIIT, was found dead in a hostel room of the university on the evening of February 16.

The police arrested one engineering student of the varsity on the charge of abetment and he is now in judicial custody since February 17.

Ten employees of KIIT were apprehended on the charge of physical assault, verbal abuse and eviction of Nepalese students from the hostel for staging protests and demanding justice over the girl's suicide.

The KIIT authorities tendered an apology over the incident.

The state government has set up a high-level committee to probe into the KIIT incident.

The Odisha government and KIIT authorities have urged the Nepalese students to return to campus and join studies with assurance of safety and dignity.

Earlier, seeking a detailed probe, the Nepal NHRC had also urged its Indian counterpart to look after the matter.

Times of India

NHRC orders probe into city univ incident

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-orders-probe-into-city-univ-incident/articleshow/118713314.cms

Debabrata Mohapatra / Mar 4, 2025, 19:50 IST

Bhubaneswar: National Human Rights Commission (NHRC) has initiated a probe into a Nepalese student's suicide and alleged harassment of other students from the Himalayan nation at a private education institute here. The commission has asked its team to submit findings by March 10.

"The commission has directed its director general (investigation) to assign a team of officers from the investigation and law divisions to conduct an on-spot inquiry at KIIT university, Bhubaneswar, and submit report by March 10," read the order. "Considering the seriousness of the matter, the commission directs its registrar (law) to proceed for inquiry in KIIT university along with team consisting of two officers from the investigation division, one not below the rank of SSP, and one officer from law division," the order stated.

NHRC's action comes after Ashutosh B, a Baramunda resident, filed a complaint recently. Nepal's human rights commission, too, had contacted its Indian counterpart seeking justice.

The third-year computer science student from Nepal was found dead in her hostel room on Feb 16 evening. Police confirmed she died by hanging following alleged harassment by a fellow student. Her death had triggered protest from Nepalese students leading to their alleged forced eviction from the university.

The incident led Nepal Prime Minister K P Sharma Oli to activate diplomatic channels to seek justice for the affected students. KIIT officials later expressed regret for the incident, while 10 staff members were arrested for assaulting Nepalese students. A high-level govt committee continues its investigation into the matter.

The Hindu

Nepali KIIT student death: NHRC orders a high level inquiry

https://www.thehindu.com/news/national/nepali-kiit-student-death-nhrc-orders-a-high-level-inquiry/article69289318.ece

Updated - March 04, 2025 06:01 pm IST - BHUBANESWAR

The Hindu Bureau

The National Human Rights Commission has directed a high-level probe into the alleged suicide by Nepali girl student and subsequent assault on Nepali students on campus of Bhubaneswar- Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), a Deemed to be University.

The apex rights panel asked its investigation team to look into other reported irregularities such as exploitation of tribal students and land illegal land acquisition by the institute.

Meanwhile, KIIT said normalcy returned to campus following the ‘unfortunate and unexpected event (suicide) on February 16.

One Asutosh B. had moved NHRC alleging that Prakriti Lamsal, a Nepali student at KIIT had faced harassment by her friend, Advik Srivastava, and that the university’s International Relations Office (IRO) had neglected her complaints, contributing to her tragic suicide.

“Protests by Nepali students seeking justice were met with verbal abuse, threats, and physical assault by KIIT officials and security guards. Moreover, KIIT and Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) were accused of exploiting tribal children, violating their human rights, and engaging in illegal land acquisitions,” the complainant filed.

He urged Commission to take action against KIIT officials, including founder Achyuta Samanta, for their failure to address harassment complaints and their involvement in the exploitation of tribal students.

The NHRC on February 28, 2025 had directed the Director General (Investigation) to assign a team of officers from the Investigation Division and Law Division of the Commission to conduct an on-spot inquiry at KIIT University and submit their inquiry report to the Commission by March 10, 2025.

Odisha asks KIIT authorities to initiate action against 'unruly' employees

Now, considering the seriousness of the matter, the Commission has directed the registrar (law) to proceed for inquiry in KIIT University, Bhubaneswar to conduct an on spot inquiry along with team consisting two officers from investigation division, one not below the rank of senior superintendent of police and one officer from Law Division and submit its inquiry report to the Commission by March, 2025.

The institute said KIIT had swiftly handed over the matter to the police for a thorough investigation and taken action against errant officials. More than 400 Nepali students have already returned to the campus, satisfied with the action taken by KIIT and arrangements made for their safety, said the institute.

“While the vice-chancellor and registrar of KIIT have issued public apologies, what remains deeply concerning is the continued negative campaign against KIIT, KISS, and its founder Achyuta Samanta,” KIIT rued.

Certain media outlets, organizations, and individuals have taken this tragedy as an opportunity to spread false narratives, amplifying the issue unnecessarily, and attempting to defame one of India’s most respected educational institutions, said university official.

KIIT announces scholarship in memory of Nepalese student

“What is particularly disheartening is the unjust treatment of the founder, whose entire life has been dedicated to the betterment of society through education and social welfare. Instead of receiving support during this trying time, he is being unjustly burdened by the weight of these attacks,” he maintained.

“KIIT has not evaded its responsibility in the matter. The founder of the institution personally addressed the concerns of Nepalese students in the presence of Nepalese Embassy officials, and the family of Prakriti Lamsal has publicly acknowledged the ongoing government efforts and the university’s cooperation,” said university in a lengthy statement.

Hindustan Times

NHRC to probe suicide case of Nepalese girl student at Odisha's KIIT University

https://www.hindustantimes.com/cities/others/nhrc-to-probe-suicide-case-of-nepalese-girl-student-at-odisha-s-kiit-university-101741094683752.html

By HT Correspondent | Mar 04, 2025 06:54 PM IST

The National Human Rights Commission has directed its officials to submit its inquiry report to the Commission by March 10

The National Human Rights Commission (NHRC) has ordered an on-spot inquiry into the death of a Nepalese girl student at KIIT University in Odisha and asked its officials to submit a report by March 10.

The NHRC issued the order while acting on a complaint that the 20-year-old student died by suicide in her hostel room in KIIT University on February 16 afternoon. The commission said that the investigation should be held by the provisions of the Protection of Human Rights Act, 1993.

"Considering the seriousness of the matter, the commission directs the Registrar (Law) to proceed for an inquiry in KIIT University, Bhubaneswar to conduct an on-spot inquiry along with a team consisting of two officers from the investigation division, one not below the rank of SSP and one officer/official from Law Division, and submit its inquiry report to the Commission by 10th March, 2025," the NHRC order said.

The complainant, Ashutosh B, in his petition, alleged that the Nepalese student at Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University, faced harassment by her "ex-boyfriend" and that the university's International Relations Office (IRO) had neglected her complaints that ended in her suicide.

He also alleged that protests by Nepalese students, who sought justice in the incident, were met with verbal abuse, threats, and physical assault by KIIT officials and security guards.

The petitioner also urged the commission to take action against KIIT officials, including founder Achyuta Samanta, for their "failure to address harassment complaints and their involvement in the exploitation of tribal students".

The police have so far arrested the main accused, a batchmate of the deceased on the charge of abetment, and he has been in judicial custody since February 17. So far 10 employees of KIIT have been apprehended on the charge of physical assault, verbal abuse and eviction of Nepalese students from the hostel for staging protests.

The state government has set up a high-level committee to probe into the KIIT incident. Though the Odisha government and KIIT authorities have urged the Nepalese students to return to campus, more than half of the students are yet to return citing safety concerns.

Meanwhile, members of the Congress Minority Cell on Tuesday staged a protest in front of the KIIT University in Bhubaneswar demanding justice for the deceased Nepali girl. They had a scuffle with the police when some of them tried to enter the University premises. Traffic in the area was halted for an hour and hundreds of vehicles were stranded on both sides of the road due to the protest.

The Hans India

NHRC team to visit Odisha's KIIT over Nepali girl student's death

https://www.thehansindia.com/news/national/nhrc-team-to-visit-odishas-kiit-over-nepali-girl-students-death-950730

IANS | 4 Mar 2025 3:15 PM IST

HIGHLIGHTS An NHRC team will visit Odisha's Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) to investigate the alleged suicide of a Nepali girl student due to harassment by her ex-boyfriend that was ignored by the college staff despite repeated complaints, a representative of the rights panel said on Tuesday.

New Delhi: An NHRC team will visit Odisha's Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) to investigate the alleged suicide of a Nepali girl student due to harassment by her ex-boyfriend that was ignored by the college staff despite repeated complaints, a representative of the rights panel said on Tuesday.

The commission has taken note of a complaint filed by Kalinga Rights Forum over the incident and formed a probe team, said NHRC Member Priyank Kanoongo.

The investigating team will verify if the student died due to suicide and her colleagues were ill-treated by the authorities when they tried to complain about the incident, said an NHRC official.

In a message on a social media platform, the complainant Forum alleged that KIIT failed to act on complaints of the Nepali girl student who was facing alleged harassment on the campus.

The deceased, Prakriti, a third-year B. Tech (Computer Science) student from Nepal, was found dead in her hostel room on February 16. While police initially registered the case as a suicide, the circumstances surrounding her death sparked protests on campus.

In the aftermath of the incident, several Nepali students fled the KIIT campus. However, later, over 150 students returned, with many re-entering India through the Raxaul border in Bihar.

The girl's death under suspicious circumstances sparked a diplomatic row between New Delhi and Kathmandu, prompting Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi to speak to Nepal's Foreign Minister, Dr Arzu Rana Deuba, and assuring strict action against those responsible.

The call followed reports that the college administration had ordered Nepali students to vacate the hostel over their protests after the incident.

During the discussion, Dr Deuba called for a fair and transparent investigation into the death of the student, identified as Prakriti Lamsal, and urged the Odisha government to ensure justice.

In response, CM Majhi reaffirmed the Odisha government's commitment to safeguarding the well-being of all students.

"Nepali students are like our own children. They will study here with full dignity and security," Majhi stated, adding that the government is closely monitoring the situation and taking necessary measures to rebuild trust among students.

The Statesman

Nepalese student's death case at Odisha's KIIT varsity: NHRC orders on-the-spot probe

The National Human Rights Commission (NHRC) ordered a high-level probe into the death of a Nepalese student and subsequent eviction of students of the Himalayan nation from Bhubaneswar-based Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University.

https://www.thestatesman.com/india/nepalese-students-death-case-at-odishas-kiit-varsity-nhrc-orders-on-the-spot-probe-1503404268.html

Statesman News Service | Bhubaneswar | March 4, 2025 1:44 pm

The National Human Rights Commission (NHRC) ordered a high-level probe into the death of a Nepalese student and subsequent eviction of students of the Himalayan nation from Bhubaneswar-based Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University.

The apex right panel, taking note of a petition filed by local resident Ashutosh B, issued a direction in this regard on Monday.

"The Commission directed the Director General (Investigation) to assign a team of officers/ officials from the Investigation Division and Law Division of the Commission to conduct an on-spot inquiry at KIIT University, Bhubaneswar, under the provisions of the Protection of Human Rights Act, 1993 and to submit their inquiry report to the Commission by March 10, 2025", the order stated.

"Considering the seriousness of the matter, the Commission directs the Registrar (Law) to proceed for inquiry in KIIT University, Bhubaneswar to conduct an on spot inquiry along with team consisting two officers from Investigation Division, one not below the rank of SSP and one officer/official from Law Division and submit its inquiry report to the Commission by 10th March, 2025," it stated.

The complainant alleged that a Nepali student at Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University, had faced harassment by her named ex-boyfriend, Advik Srivastava, and that the university's International Relations Office (IRO) had neglected her complaints, contributing to her tragic suicide, the order mentioned.

Protests by Nepali students seeking justice were met with verbal abuse, threats, and physical assault by KIIT officials and security guards. Additionally, the complainant accused Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University and Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) of exploiting tribal children, violating their human rights, and engaging in illegal land acquisitions. A 2017 Child Welfare Committee report revealed poor living conditions at Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), including overcrowding, unclean facilities, and lack of basic amenities, the order quoting the contents of the petition noted.

The complainant urged the commission to take action against KIIT officials, including founder Achyuta Samanta, for their failure to address harassment complaints and their involvement in the exploitation of tribal students, according to the NHRC order uploaded on the Commission's website.

Around 2000 foreign students from 65 countries are enrolled in KIIT, which is widely regarded as one of the premier private universities in the country. Sizable bulks of the foreign students are from the Himalayan nation. The varsity has an overall roll strength of 40,000 students, including those from foreign countries. Allegations of grabbing of 12 acre-patch government land were earlier leveled against the private university founded by former BJD MP Samanta.

A 20-year-old engineering student from Nepal was found dead in her hostel room on 16 February, triggering widespread student unrest.

The visuals of students of Nepal being forcibly evicted from the university hostel and being manhandled later went viral on social media platforms, drawing outrage from several quarters, including the Nepal PM and diplomats of the neighbouring country.

A visibly embarrassed Odisha Government later constituted a high-level inquiry fact-finding committee to probe the incident, which the Government described as 'most unfortunate'. The governmental inquiry into the KIIT episode is still in progress, and its findings are yet to be made public.

Bar and Bench

NHRC takes cognizance of dog bite menace

5 lakh child victims of dog bites in 2024: NHRC takes cognizance

Over 21 lakh dog bite incidents were reported in 2024, which resulted in 37 deaths, as per a Lok Sabha response.

https://www.barandbench.com/news/5-lakh-child-victims-of-dog-bites-in-2024-nhrc-takes-cognizance

Ratna Singh | Published on: 04 Mar 2025, 6:50 am

2 min read

The National Human Rights Commission (NHRC) recently directed the Animal Welfare Board, Haryana to investigate dog bite cases in the State and submit an Action Taken Report (ATR).

The incident came to light after a news article published data provided by the Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying in the Lok Sabha highlighting that approximately 21,95,122 dog bite incidents were reported in 2024. 5 lakh of the victims were children, whereas 37 deaths were recorded.

The complainant, Anubhava Shrivastava Shahai, in her letter to the NHRC highlighted the gravity of the issue, calling it a complete failure on the part of state governments.

She criticised authorities for not effectively controlling the stray dog population and flagged the issues of irregular sterilisation and inadequate infrastructure for implementing the Animal Birth Control (ABC) Guidelines.

Additionally, she said that the lack of animal shelter homes to keep aggressive and ferocious dogs under observation, as mandated by the 2023 ABC Guidelines, has worsened the situation. As a result, the stray dog population continues to grow, causing distress to citizens, she said.

She further stated that central, state, and local-level monitoring committees are either not functioning properly or may not have been constituted in every state and district.

Urging immediate action, she requested cognizance of the issue and called for notices to be issued to the Animal Welfare Board of India (AWBI) and all states to take prompt measures to protect citizens.

Taking cognizance of the same, NHRC Assistance Registrar (Law) Brijvir Singh ordered,

"Let the complaint be transmitted to the Chairman, Animal Welfare Board of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Faridabad, Haryana, with directions to get the allegations made in the complaint looked into and to submit an Action Taken Report within four weeks for perusal of the Commission."

It was further directed that a copy of the complaint/intimation be forwarded as an attachment for necessary action in accordance with the Commission's directions. An Action Taken Report is requested to be submitted to the Commission within four weeks from the date of receipt of this letter.

The News Minute

NHRC orders probe into rising dog bite cases in Haryana

According to the Ministry of Animal Husbandry, in 2024 alone, nearly 21.95 lakh dog bite cases were recorded, including five lakh children among the victims.

https://www.thenewsminute.com/news/paytm-shares-plunge-over-3-pc-after-ed-issues-notice-over-fema-violations

Written by: TNM Staff | Published on: 04 Mar 2025, 4:02 pm

The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Animal Welfare Board in Haryana to investigate the rising incidents of dog bites across the state and submit a report on the measures taken to address the issue. The direction comes after a news report citing data presented in the Lok Sabha by the Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying, revealed that in 2024 alone, nearly 21.95 lakh dog bite cases were recorded, including five lakh children among the victims. Further, 37 fatalities were also reported.

According to the Bar and Bench, a complaint was filed to the NHRC by Anubhava Shrivastava Shahai, raising serious concerns about the issue, condemning the state governments for their failure to address the crisis effectively. She pointed out lapses in stray dog population control, citing inconsistent sterilization efforts and insufficient infrastructure to implement the Animal Birth Control (ABC) guidelines properly. She also highlighted the absence of adequate shelter homes to house aggressive or dangerous stray dogs for observation, a requirement under the 2023 ABC Guidelines. This deficiency, she argued, has exacerbated the problem, leading to a continuous rise in the stray dog population and increasing distress among residents.

Shahai also noted that monitoring committees at central, state, and local levels were either non-functional or, in some instances, absent in certain states and districts. Seeking urgent intervention, she urged authorities to issue notices to the Animal Welfare Board of India (AWBI) and all state governments, calling for immediate action to address the situation.

In response, NHRC Assistant Registrar (Law) Brijvir Singh instructed that the matter be referred to the Chairman of the Animal Welfare Board of India, under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying in Faridabad, Haryana. The board has been directed to investigate the concerns raised in the complaint and submit an Action Taken Report within four weeks. Additionally, the Commission ordered that a copy of the complaint be forwarded for necessary action as per its directives.

Bar and Bench

2024 में 5 लाख बच्चे कुत्तों के काटने के शिकार होंगे: एनएचआरसी ने संज्ञान लिया

लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार, 2024 में कुत्तों के काटने की 21 लाख से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 37 मौतें हुईं।

https://hindi.barandbench.com/news/5-lakh-child-victims-of-dog-bites-in-2024-nhrc-takes-cognizance

Bar & Bench | Published on: 04 Mar 2025, 12:48 pm

2 min read

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हाल ही में पशु कल्याण बोर्ड, हरियाणा को राज्य में कुत्तों के काटने के मामलों की जांच करने और कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

यह घटना तब प्रकाश में आई जब एक समाचार लेख में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को प्रकाशित किया गया, जिसमें बताया गया कि 2024 में लगभग 21,95,122 कुत्तों के काटने की घटनाएं दर्ज की गईं। पीड़ितों में से 5 लाख बच्चे थे, जबकि 37 मौतें दर्ज की गईं।

शिकायतकर्ता, अनुभव श्रीवास्तव शाहई ने NHRC को लिखे अपने पत्र में इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर किया, इसे राज्य सरकारों की ओर से पूरी तरह से विफलता बताया।

उन्होंने आवारा कुत्तों की आबादी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं करने के लिए अधिकारियों की आलोचना की और अनियमित नसबंदी और पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के मुद्दों को उठाया।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि 2023 एबीसी दिशानिर्देशों के अनुसार आक्रामक और क्रूर कुत्तों को निगरानी में रखने के लिए पशु आश्रय गृहों की कमी ने स्थिति को और खराब कर दिया है। नतीजतन, आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ती जा रही है, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की निगरानी समितियां या तो ठीक से काम नहीं कर रही हैं या फिर हर राज्य और जिले में उनका गठन नहीं किया गया है।

उन्होंने तत्काल कार्रवाई का आग्रह करते हुए मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया और नागरिकों की सुरक्षा के लिए त्वरित कदम उठाने के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) और सभी राज्यों को नोटिस जारी करने का आह्वान किया।

इसका संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी के सहायक रजिस्ट्रार (कानून) बृजवीर सिंह ने आदेश दिया,

"शिकायत को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, फरीदाबाद, हरियाणा के अध्यक्ष को इस निर्देश के साथ भेजा जाए कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जाए और आयोग के अवलोकन के लिए चार सप्ताह के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।"

यह भी निर्देश दिया गया कि शिकायत/सूचना की एक प्रति आयोग के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुलग्नक के रूप में भेजी जाए। इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

Amar Ujala

Odisha: मानवाधिकार आयोग ने KIIT में नेपाली छात्र की मौत की जांच के दिए आदेश, 10 मार्च तक मांगी रिपोर्ट

https://www.amarujala.com/india-news/odisha-nhrc-orders-probe-into-nepalese-student-s-death-at-kiit-seeks-report-by-mar-10-news-in-hindi-2025-03-04

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर Published by: पवन पांडेय Updated Tue, 04 Mar 2025 03:03 PM IST

सार

देश

ओडिशा के केआईआईटी विश्वविद्यालय में नेपाली छात्रा की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त हो गया है। मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं और 10 मार्च तक इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

विस्तार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा के केआईआईटी विश्वविद्यालय में एक नेपाली छात्रा की मौत की मौके पर जाकर जांच करने का आदेश दिया है और अपने अधिकारियों से 10 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एनएचआरसी ने यह आदेश एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 20 वर्षीय छात्रा ने 16 फरवरी को अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या करके मौत हो गई थी। आयोग ने कहा कि जांच मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए।

10 मार्च तक आयोग को सौंपी जाए रिपोर्ट- NHRC

आयोग के आदेश में कहा गया है, 'मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग रजिस्ट्रार (कानून) को केआईआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में जांच के लिए आगे बढ़ने का निर्देश देता है, ताकि जांच प्रभाग के दो अधिकारियों, जिनमें से एक एसएसपी के पद से नीचे का न हो और एक अधिकारी/कर्मचारी विधि प्रभाग से हो, की एक टीम के साथ मौके पर जाकर जांच की जाए और 10 मार्च, 2025 तक आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए।'

शिकायतकर्ता ने क्या-क्या लगाए आरोप?

शिकायतकर्ता आशुतोष बी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालय में नेपाली छात्रा को उसके पूर्व प्रेमी की तरफ से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय (आईआरओ) ने उसकी शिकायतों की अनदेखी की, जिसके कारण उसने दुखद आत्महत्या कर ली। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि घटना में न्याय की मांग करने वाले नेपाली छात्रों के विरोध प्रदर्शन का सामना केआईआईटी अधिकारियों और सुरक्षा गार्डों की तरफ से मौखिक दुर्व्यवहार, धमकियों और शारीरिक हमले के साथ किया गया।

याचिकाकर्ता ने आयोग से संस्थापक अच्युत सामंत सहित केआईआईटी अधिकारियों के खिलाफ 'उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने में विफलता और आदिवासी छात्रों के शोषण में उनकी संलिप्तता' के लिए कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, केआईआईटी में तीसरे वर्ष की कंप्यूटर साइंस की छात्रा16 फरवरी की शाम को विश्वविद्यालय के छात्रावास के कमरे में मृत पाई गई। पुलिस ने विश्वविद्यालय के एक इंजीनियरिंग छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया और वह अब 17 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है। वहीं इस मामले में केआईआईटी के दस कर्मचारियों को नेपाली छात्रों पर शारीरिक हमला, मौखिक दुर्व्यवहार और छात्रा की आत्महत्या पर न्याय की मांग करने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए छात्रावास से बाहर निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। केआईआईटी अधिकारियों ने इस घटना पर माफी मांगी।

नेपाली एनएचआरसी ने भारत से की अपील

इस मामले में राज्य सरकार ने केआईआईटी घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ओडिशा सरकार और केआईआईटी अधिकारियों ने नेपाली छात्रों से परिसर में लौटने और सुरक्षा और सम्मान के आश्वासन के साथ पढ़ाई में शामिल होने का आग्रह किया है। इससे पहले, विस्तृत जांच की मांग करते हुए नेपाली एनएचआरसी ने भी अपने भारतीय समकक्ष से मामले को देखने का आग्रह किया था।

Bharat Express

ओडिशा के कीट विश्वविद्यालय में नेपाली छात्र की मौत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा जांच

ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कीट विश्वविद्यालय में एक नेपाली छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. इस मामले को लेकर NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने प्रतिक्रिया दी है.

https://bharatexpress.com/india/nepali-student-dies-in-odishas-kiit-university-national-human-rights-commission-to-investigate-479556

Written by मिताली चंदोला, एडिटर, स्पेशल प्रोजेक्ट्स March 4, 2025 2:19 pm

ओडिशा के कीट विश्वविद्यालय में नेपाली छात्र की मौत

KIIT Student Death:ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कीट विश्वविद्यालय में एक नेपाली छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आयोग को इस घटना को लेकर एक शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायत कलिंगा राइट्स फोरम नामक संगठन द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि नेपाली छात्र की मौत आत्महत्या के कारण हुई है. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह आत्महत्या थी या किसी अन्य कारण से हुई मौत.

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नेपाली छात्रों ने इस घटना के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तो उनके साथ मारपीट की गई. इन गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक विशेष टीम गठित की है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी. प्रियंक कानूनगो ने बताया कि यह टीम जल्द ही विश्वविद्यालय का दौरा करेगी और विस्तृत जांच के बाद 10 मार्च से पहले आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ रहा है और नेपाली छात्र समुदाय में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. मानवाधिकार आयोग की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि नेपाली छात्र की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और वजह थी. साथ ही, नेपाली छात्रों के साथ कथित मारपीट के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की जाएगी. फिलहाल, इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

-भारत एक्सप्रेस

Navbharat Live

Odisha News: ओडिशा के KIIT में नेपाली छात्रा की मौत पर बड़ा एक्शन, NHRC ने दिए जांच के आदेश, जानिए सभी अपडेट्स।

NHRC ने अपनी जांच के लिए एक विशेष दल गठित किया है, जांच मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत होगी। जांच का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि KIIT छात्रा की आत्महत्या की असली वजह क्या थी।

https://navbharatlive.com/india/odisha-newsbig-action-death-of-nepali-student-in-odishas-kiit-nhrc-orders-investigation-know-all-updates-1144210.html

By सौरभ शर्मा | Updated On: Mar 04, 2025 | 04:22 PM

भुवनेश्वर: ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) विश्वविद्यालय में पढ़ रही नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल की रहस्यमयी मौत ने नया मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि 10 मार्च 2025 तक इस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रा की उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को नजरअंदाज किया, जिसके चलते यह दुखद घटना हुई।

NHRC की टीम करेगी गहन जांच

NHRC ने अपनी जांच के लिए एक विशेष दल गठित किया है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) स्तर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होगा और विधि प्रभाग का एक अधिकारी भी शामिल रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह जांच मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत होगी। जांच का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि छात्रा की आत्महत्या की असली वजह क्या थी और क्या उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने यह कदम उठाया।

पूर्व प्रेमी पर उत्पीड़न का आरोप, सुरक्षा गार्डों पर हमले के दावे

शिकायतकर्ता आशुतोष बी की याचिका के अनुसार, 20 वर्षीय प्रकृति लामसाल ने 16 फरवरी को अपने हॉस्टल के कमरे में कथित रूप से आत्महत्या कर ली। आरोप लगाया गया है कि उसका पूर्व प्रेमी उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, लेकिन जब उसने इसकी शिकायत विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध कार्यालय (IRO) से की, तो इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। यही नहीं, घटना के बाद जब नेपाली छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, तो विश्वविद्यालय प्रशासन और सुरक्षा गार्डों ने उनके साथ बदसलूकी की, धमकाया और कई छात्रों को हॉस्टल से बाहर कर दिया।

KIIT प्रशासन पर गंभीर आरोप, दस कर्मचारी गिरफ्तार

इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। KIIT संस्थापक अच्युत सामंत सहित अन्य अधिकारियों पर आदिवासी और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के शोषण का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने विश्वविद्यालय के एक इंजीनियरिंग छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 17 फरवरी से न्यायिक हिरासत में रखा है। इसके अलावा, नेपाली छात्रों पर हमले के आरोप में विश्वविद्यालय के 10 कर्मचारियों को

भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए KIIT प्रशासन ने माफी मांगी थी और ओडिशा सरकार ने नेपाली छात्रों को सुरक्षा और सम्मान का भरोसा दिलाते हुए उन्हें कक्षाओं में लौटने की अपील की गई थी। अब NHRC की जांच से यह साफ होगा कि आखिर यह आत्महत्या थी या किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा।

Devdiscourse

Calls for Justice: Brutal Murder Uncovers Corruption in Beed

Bajrang Sonawane, an NCP Lok Sabha member, demanded evidence of brutality against sarpanch Santosh Deshmukh be submitted to the NHRC. Deshmukh was murdered after opposing an extortion bid. This incident led to the resignation of NCP leader Dhananjay Munde as further evidence of the crime emerged.

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3284867-calls-for-justice-brutal-murder-uncovers-corruption-in-beed

Devdiscourse News Desk | Chhatrapatisambhajinagar | Updated: 04-03-2025 15:09 IST | Created: 04-03-2025 15:09 IST

Bajrang Sonawane, an NCP Lok Sabha member, has urged the Beed collector and police to provide photos documenting the brutality against sarpanch Santosh Deshmukh to the National Human Rights Commission (NHRC).

This demand comes in the wake of Dhananjay Munde's resignation as state cabinet minister, following revelations that his associate Walimk Karad masterminded Deshmukh's murder.

Deshmukh faced a gruesome fate as he was kidnapped, tortured, and murdered for resisting an extortion attempt directed at an energy company in Beed. The CID's chargesheet, replete with videos and photos of the atrocities, underscores the murder's severity and has intensified calls for justice and accountability.

(With inputs from agencies.)

ETV Bharat

Beed Authorities Should Submit To NHRC Pics Of Sarpanch's Torture: MP Sonawane

Bajrang Sonawane said the Beed collector and police should submit photos of brutality inflicted on sarpanch Santosh Deshmukh to the NHRC.

https://www.etvbharat.com/en/!state/beed-authorities-should-submit-to-nhrc-pics-of-sarpanch-torture-says-mp-sonawane-enn25030403671

By PTI | Published : Mar 4, 2025, 9:46 PM IST

1 Min Read

Chhatrapati Sambhajinagar: NCP (SP) Lok Sabha member Bajrang Sonawane on Tuesday said the Beed collector and police should submit photos of brutality inflicted on sarpanch Santosh Deshmukh to the National Human Rights Commission (NHRC). Notably, NCP leader Dhananjay Munde resigned as the state cabinet minister on Tuesday, days after his close aide Walmik Karad was named as the mastermind in the sarpanch murder case.

Deshmukh, the sarpanch of Massajog village in Beed, was abducted, tortured and murdered on December 9 last year, allegedly for attempting to stop an extortion bid targeting an energy company in the district. The opposition doubled down on its demand for Munde’s resignation after gory photos and court chargesheet details related to the killing surfaced, revealing the brutalities committed before the murder.

As Deshmukh was tortured and killed last year, the assailants recorded 15 videos, clicked eight photos and even made two video calls, police have said in a chargesheet, documenting the brutality endured by the victim. The videos and the photos are part of the chargesheet submitted by the Crime Investigation Department (CID) before a court in central Maharashtra's Beed district last week.

Amar Ujala

Beed Sarpanch Murder Case: 'जांच अधिकारी NHRC को सौंपें यातना की तस्वीरें'; एनसीपी सांसद सोनवणे ने की मांग

https://www.amarujala.com/india-news/beed-sarpanch-murder-case-ncp-mp-bajrang-sonawane-santosh-deshmukh-torture-photo-nhrc-news-updates-in-hindi-2025-03-04

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 04 Mar 2025 04:46 PM IST

सार

देश

महाराष्ट्र के बीड में सरपंच की हत्या का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सांसद बजरंग सोनवणे ने कहा, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को सरपंच को दी गई यातना की तस्वीरें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सौंपनी चाहिए।

विस्तार

महाराष्ट्र के बीड में हुई सरपंच की नृशंस हत्या की गुत्थी सुलझनी बाकी है। ताजा घटनाक्रम में इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों से सरपंच को दी गई यातना की तस्वीरें मांगी गई हैं। विपक्षी खेमे के सांसद बजरंग सोनवणे ने कहा कि जांच अधिकारियों को क्रूरता की तस्वीरें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सौंपनी चाहिए। सांसद के बयान से पहले मंगलवार को अहम घटनाक्रम में सत्ताधारी खेमे से जुड़े एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया।

NHRC को क्रूरता के साक्ष्य दिखाएं जांच अधिकारी

बता दें कि बीड के सांसद सोनवणे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार (NCP-SP) के सांसद हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि बीड कलेक्टर और पुलिस को सरपंच संतोष देशमुख के साथ की गई क्रूरता के साक्ष्य एनएचआरसी को दिखाने चाहिए। उन्होंने सरपंच के भाई धनंजय देशमुख और अन्य स्थानीय लोगों से मासजोग गांव जाकर मुलाकात की।

मानवाधिकार आयोग बीड में क्ररता की जांच करेगा

सरपंच के परिजनों से मुलाकात के बाद सोनवणे ने पत्रकारों से कहा, 'मैंने सरपंच की हत्या के आठ दिन बाद इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की। मुझे पता था कि यह कैसे हुआ। आयोग ने बीड एसपी और कलेक्टर को एक पत्र लिखा। अब जांच अधिकारियों को तस्वीरें संलग्न कर आयोग को जवाब भेजना चाहिए। मानवाधिकार आयोग की एक टीम निश्चित रूप से जांच के लिए यहां आएगी।'

NHRC को कौन से सबूत सौंपने की बात हो रही है?

हत्या से संबंधित खूनी तस्वीरें और अदालती चार्जशीट के विवरण सामने आने के बाद विपक्ष ने मुंडे पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया, जिसके कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा।

इन सबूतों के सामने आने के बाद हत्या से पहले की गई क्रूरताओं का खुलासा हुआ। जांच कर रही पुलिस ने आरोपपत्र में कहा है कि पिछले साल जब देशमुख को प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या की गई, तो हमलावरों ने 15 वीडियो रिकॉर्ड किए, आठ तस्वीरें खींची और दो वीडियो कॉल भी किए। ये वीडियो और तस्वीरें पिछले सप्ताह बीड की एक अदालत में पेश किए गए। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने इसे अपने आरोपपत्र का हिस्सा बनाया है।

सरपंच की हत्या का मास्टरमाइंड कौन?

गौरतलब है कि बीड के मासजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख को अगवा और प्रताड़ित किए जाने के बाद पिछले साल दिसंबर में मौत के घाट उतार दिया गया था। पिछले साल 9 दिसंबर को कथित तौर पर जिले में एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर जबरन वसूली की कोशिश हो रही थी। जांच में सामने आई बातों के मुताबिक वसूली रोकने का प्रयास करने के कारण देशमुख को अपनी जान गंवानी पड़ी। जांच अधिकारियों ने कुछ दिनों पहले धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड को सरपंच हत्या मामले में मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया था।

The Probe

Bonded Labour Crisis: NHRC Slams Punjab Government's Flawed Probe

Bonded Labour Crisis: The NHRC slammed the Punjab government for a flawed probe into the rescue of bonded labourers in Moga. The Commission has sought a report by April 7.

https://theprobe.in/human-rights/bonded-labour-crisis-nhrc-slams-punjab-governments-flawed-probe-8788190

By Prema Sridevi 04 Mar 2025

Bonded Labour Crisis in Moga Sparks NHRC Fury

A human rights crisis that captured national attention last month has taken a dramatic turn, with the National Human Rights Commission (NHRC) delivering a sharp rebuke to the Moga district administration. The NHRC has accused the Moga authorities in Punjab of conducting a flawed investigation into the alleged enslavement of 56 bonded labourers, including women and children, at Sandhu Brick Kiln Industries in Patti Sandhuan village, Moga.

The Probe has accessed the NHRC's letter, dated February 28, 2025, which demands a thorough re-examination of the case. In its communication to the Punjab Labour Commissioner and the Moga District Magistrate, the Commission noted that the report from the Additional District Magistrate, Moga, is riddled with numerous loopholes and is misleading.

We are a small, dedicated team at The Probe, committed to in-depth, slow journalism that dives deeper than daily headlines. We can't sustain our vital work without your support. Please consider contributing to our social impact projects: Support Us or Become a Member of The Probe. Even your smallest support will help us keep our journalism alive.

The saga unfolded in January 2025 when Ankush Kumar, a 26-year-old bonded labourer risked his life and escaped from the brick kiln in Moga to inform The Probe about the plight of 56 individuals—including women and children—trafficked from Uttar Pradesh to Punjab. Another bonded labourer, Arvind Kumar, also fled the Moga brick kiln to speak with The Probe. In his video interview, Kumar revealed that around 19 children, along with their families, were being forced to work against their will at the kiln. The Probe teamed up with Nirmal Gorana, Convenor of the National Campaign Committee for Eradication of Bonded Labour (NCCEBL), and met several more rescued bonded labourers in Banhera Khas village, Saharanpur, Uttar Pradesh. This visit enabled us to trace the missing bonded labourers from Saharanpur.

Meanwhile, Gorana sent a letter to the NHRC outlining the dire situation of the bonded labourers in Moga, who were working at Sandhu Brick Kiln Industries. Gorana's letter included comprehensive details, listing the names of all 56 bonded labourers from 10 families and specifying the advances each family had allegedly received from the brick

kiln owner. Some had taken as little as 10,000 rupees, pledging themselves and their entire families to work at the kiln without pay for months, according to Gorana.

All the labourers, members of the Scheduled Caste (SC) community, were allegedly subjected to grueling work without wages to repay debts. The Probe's January investigation and Gorana's letter to the NHRC spurred a rescue operation by the Moga district administration. As a result, in the first week of February, 46 labourers from eight families were freed, though two families remained unaccounted for. During the rescue, the Moga district administration recorded statements from the bonded labourers, including children, who clearly described the grueling conditions and human rights violations they had endured for so long.

Stay informed with The Probe. Get original stories, exclusive insights, and thoughtful, in-depth analysis delivered straight to your phone. Join our WhatsApp channel now! Click the link to join: https://whatsapp.com/channel/0029VaXEzAk90x2otXl7Lo0L

Yet, the Moga administration's action taken report, submitted on February 6 by the Additional District Commissioner (ADC), was filled with misleading information. The ADC reported that a five-member committee, including representatives from the DSP's office, Moga, Civil Surgeon Moga, ALC Moga, and the District Child Protection Officer, Moga, visited the brick kiln in question. All 56 members from 10 families were identified, though two families were absent, having left the site of their own accord. Statements were recorded from the remaining eight families present at the kiln. The household heads expressed their desire to return home, requesting they be sent back after receiving outstanding wages for their work. The ADC claimed that, based on these statements, the committee concluded the families named in the complaint were not held as bonded labourers at the kiln.

The NHRC, however, isn't convinced. In a strongly worded letter to the Punjab government, the commission dismantled the report's credibility. "The report has several loopholes and is misleading," wrote Assistant Registrar Brijvir Singh from the NHRC, questioning how the committee could dismiss bonded labour without verifying compliance with labour laws or confirming payment of outstanding wages. The committee hurriedly sent all families back to their homes without determining whether the labourers had received their due wages.

The NHRC expressed dissatisfaction with the inquiry conducted by the committee, noting its apparent "lack of expertise in labour laws" and criticising the Moga administration for concluding the workers were not bonded labourers despite their claims of unpaid dues. The commission emphasised that bonded labour, by definition, involves forced work without wages or to repay debt—conditions the labourers themselves alleged. It has demanded answers by April 7 on seven critical points, including whether the kiln was licensed, wages were paid, and basic amenities like schooling and healthcare were provided.

The Commission in its letter asked the Moga administration to forward legible copies of the wage register, muster roll, wage slips, and copies of registers required under various labour legislations (Payment of Wages Act, Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act). In the absence of these mandated documents and the benefits required by law, the District Magistrate is obligated to presume that the labourers are bonded labourers.

It further questioned whether the brick kiln owner complied with all provisions of the Minimum Wages Act, 1948, and its associated rules. If not, what actions were taken? Were the labourers provided with basic amenities such as schooling for children, medical and healthcare services, food, water, sanitation/toilets, and proper accommodation by the employer? Beyond these, were the released bonded labourers granted benefits under government welfare schemes like MGNREGA, housing, ration cards, and education, as outlined in the Ministry of Labour and Employment's directive dated May 18, 2016? Was the Vigilance Committee, mandated under Section 13 of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, constituted? If not, why? If it is operational, since when? Did members of the Vigilance Committee from SC and ST communities accompany the team? If not, the reasons must be explained, the NHRC asserted in its letter.

"This is a Travesty of Justice"

“This is a travesty of justice,” said Nirmal Gorana, convener of the NCCEBL and the complainant who initially brought the case to the NHRC’s attention. “These families were trafficked, exploited, and now abandoned by a system meant to safeguard them. The administration’s haste to exonerate itself has deprived them of justice and rehabilitation,” Gorana told The Probe.

Gorana elaborated: “Two bonded labourers told The Probe on camera that they escaped to seek help. All the bonded labourers approached me and requested our organisation’s support for their rescue. We even obtained videos from inside the brick kiln showing some of them pleading for assistance. Children were being forced into labour there. The brick kiln owner withheld wages, prevented them from leaving, and compelled them to work for free. Some labourers reported physical and verbal abuse and being forced to work against their will without pay. Why did the Moga district administration choose to whitewash this case and declare them not bonded labourers? Clearly, the government wants to conceal the disgrace that such a shameful bonded labour system existed in their jurisdiction. What about justice for these impoverished labourers?” Gorana questioned.

The NHRC’s intervention highlights a systemic failure. Bonded labour, prohibited under the Bonded Labour System (Abolition) Act of 1976, persists as a widespread scourge in India, often concealed by debt traps and informal employment. The Moga case exemplifies this pattern: families enticed by agents with advance payments, only to be trapped in perpetual servitude. Yet, the administration’s response reflects a disturbing trend—recasting such cases as mere labour disputes rather than human rights violations, a strategy experts say evades accountability and the issuance of release certificates.

The Commission's critique poses sharp questions. Did Sandhu Brick Kiln Industries possess a valid license? Were wage registers, muster rolls, or other required records kept? The NHRC contends that the absence of such documentation should legally presume bonded labour. Furthermore, the committee neglected to verify whether the labourers received their dues before being sent away—an oversight that risks driving them back into exploitation. "Sending them home without wages or support isn't rescue; it's abandonment," Gorana stated.

Children, the most vulnerable in this crisis, remain a critical concern. The NHRC had mandated their immediate rescue and presentation to the Child Welfare Committee under the Juvenile Justice Act and Child Labour Act. However, the Moga report skirts their fate, providing no evidence of rehabilitation or safeguards against further trafficking—a blatant breach of the NHRC's directive.

The rescued families, now returned to Uttar Pradesh, confront an uncertain future without government assistance such as MGNREGA benefits, housing, or ration cards, which the NHRC insists must be provided under a 2016 Ministry of Labour scheme. "Rescue is meaningless without rehabilitation," Gorana stressed.

"These families need a lifeline, not just a truck ride home. The administration's denial shields the powerful—kiln owners, contractors, and a corrupt supply chain—while the poor are left to fend for themselves. The Moga district administration should have recorded the statements of each labourer and soon after the rescue, they should have issued release certificates to the bonded labourers. This could have helped them get access to rehabilitation packages from the government. Instead, the district administration decided to hide the existence of such a heinous crime in their jurisdiction. This will yet again push these rescued labourers into the vicious cycle of bondage," stated Gorana.

The Moga administration has stayed silent, with the District Magistrate unavailable for comment as of March 4. Meanwhile, Sandhu Brick Kiln Industries has issued no public statement, leaving the owner and agents unaccountable—for the moment.

The NHRC's April 7 deadline looms as a critical test of whether Punjab will uphold justice or persist in evasion. As the commission probes further, the Moga bonded labour crisis serves as a grim reminder: modern slavery flourishes not only in brick kilns but also in the shadows of bureaucratic indifference. For the 46 rescued—and the 10 still unaccounted for—the struggle for dignity remains far from resolved.

Orissa Post

NHRC seeks ATR on plight of Juang tribal community

https://www.orissapost.com/nhrc-seeks-atr-on-plight-of-juang-tribal-community/

PNN | Updated: March 4th, 2025, 09:43 IST

Keonjhar: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of a complaint and sought an Action Taken Report (ATR) from the District Magistrate-cum-Collector of Keonjhar, regarding alleged human rights violations affecting the Juang Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG). The commission has directed officials to submit the report within four weeks.

The NHRC issued the order Friday after reviewing a petition filed by human rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy. The petition alleges that negligence and apathy on part of state's ST & SC Development, Minorities & Backward Classes Welfare department and the Keonjhar district administration have resulted in severe hardships for the Juang PVTG community, including lack of all-weather roads, healthcare, and education.

Tripathy further alleged that many villages lack basic infrastructure, forcing residents to transport patients on makeshift cots. Despite Keonjhar district having one of the highest allocations from the District Mineral Foundation (DMF) funds, authorities have failed to address these pressing needs, he claimed.

The petition highlighted the plight of Juang tribesmen living in 114 villages without basic amenities. The Juangs are one of the 13 PVTGs among the 62 tribal communities found in Odisha, who primarily reside in and around the Gonasika Hill area of Banspal block in Keonjhar district.

Citing a specific case, Tripathy reported that due to inadequate healthcare facilities, 35-year-old Sunia Juanga, his wife Rashmi, 30, and their 6-month-old daughter, Nani, died in Jantari village. Their three surviving children are now orphaned. The petition alleged that health services are virtually nonexistent, with the nearest primary health centre located 15 km away and the block headquarters at about 40 km distance. A few Juang families benefit from the state-sponsored Biju Swasthya Kalyan Yojana (BSKY) or the National Health Card, the complaint stated.

Additionally, the petition contended that there is no official database tracking minor orphans or child marriages within the Juang community. It accused state authorities of negligence and inaction, raising serious human rights concerns.

The petition further alleged that due to administrative failure, Juang orphans are left without access to even basic necessities. It cited government inaction, corruption, and systemic neglect as contributing to the deprivation and suffering of the PVTG Juang community.

PNN

North East News

Congress slams 'police raj' in Assam, urges Supreme Court to act on encounter killings

The government maintained that police cases were registered for each incident in accordance with relevant laws and the guidelines of the NHRC

https://nenews.in/assam/congress-slams-police-raj-in-assam-urges-supreme-court-to-act-on-encounter-killings/21248/

By Northeast News | March 4, 2025

Guwahati: The Congress on Tuesday criticised the BJP-led government in Assam, accusing it of operating a "police raj" following revelations that 72 accused individuals have been killed and 220 injured in police actions since Chief Minister Himanta Biswa Sarma assumed office in May 2021.

The data, tabled in the state assembly by Sarma, who also holds the home portfolio, documented 256 instances of police action during this period.

Magisterial inquiries were conducted in 175 of these cases, with the remaining 81 lacking such probes.

The government maintained that police cases were registered for each incident in accordance with relevant laws and the guidelines of the National Human Rights Commission (NHRC).

However, Congress Leader of Opposition Debabrata Saikia urged the Supreme Court to take suo motu cognizance of the data while deliberating on an ongoing case regarding alleged fake encounters in Assam.

Saikia emphasised that the apex court should include the recent findings in its review before delivering a verdict.

According to documents tabled in the assembly, 38 people died in police custody during remand, while another 34 were killed before being placed in remand.

The data also highlighted 181 individuals who sustained bullet injuries while in remand and 40 more who were injured prior to remand.

Saikia alleged that the statistics pointed to a blatant disregard for the rule of law and accused the ruling party of using police forces for political purposes.

A year-wise breakdown revealed that 2021 saw the highest number of fatalities, with 31 people killed and 67 injured in 83 cases of police action.

Magisterial inquiries were ordered in 52 of these cases. In 2022, 18 accused were killed, and 79 injured in 95 incidents, with 66 of these cases subjected to inquiries.

The trend continued in 2023 and 2024, with additional deaths and injuries recorded.

The opposition had earlier accused the Assam Police of being “trigger happy,” claiming the force was engaging in “open killings” under Sarma’s administration.

Another set of documents showed that 136 people had been killed across Assam in police actions since 2016, when the BJP first came to power in the state.

The Supreme Court was recently informed by the Assam government that it had adhered to the 2014 guidelines for investigating police encounters.

However, a bench of Justices Surya Kant and N Kotiswar Singh reserved its verdict on a plea seeking an independent investigation into 171 alleged fake encounters in Assam between May 2021 and August 2022, in which 56 people were killed and 145 injured.

Petitioner Arif Md Yeasin Jwadder challenged a Gauhati High Court order dismissing his PIL regarding these encounters.

Last October, the Supreme Court termed the situation “very serious” and requested detailed information on the probes conducted in such cases.

Insamachar

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए मिशन संचालन समूह की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की

https://insamachar.com/union-health-minister-jp-nadda-chairs-the-9th-meeting-of-the-mission-steering-group-for-national-health-mission/

Editor Posted on 4 मार्च 2025

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की नौवीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव और अनुप्रिया पटेल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी, नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल भी उपस्थित थे।

मिशन संचालन समूह एनएचएम के तहत सर्वोच्च नीति-निर्माण और संचालन संस्था है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए व्यापक नीति निर्देश और शासन प्रदान करती है। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष, पेयजल एवं स्वच्छता, पंचायती राज, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिवों के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, आवास एवं शहरी मामले, व्यय विभाग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारी, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा सहित उच्च केन्द्र बिंदु वाले राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए एनएचएम की उपलब्धियों की सराहना की और विभिन्न पहलों और योजनाओं के परिणाम सुनिश्चित करने में एमएसजी की भूमिका के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने "विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के एजेंडे और उद्देश्यों को सुनिश्चित करने" की आवश्यकता पर जोर देते हुए जमीनी स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) जैसे अधिकारियों की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने प्रशासनिक बाधाओं का हवाला देते हुए "मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाने, मजबूत करने" और "प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता" का सुझाव दिया ताकि उनकी क्षमताओं का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग किया जा सके। यह जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जमीनी स्तर पर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका की भी सराहना की तथा नियमित गतिविधियों के लिए संशोधित प्रोत्साहनों और बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान करके उनके और अधिक सशक्तीकरण एवं कल्याण की आवश्यकता पर बल दिया।

जेपी नड्डा ने नई प्रौद्योगिकीय प्रगति और परिवर्धन के माध्यम से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किए गए विकास की सराहना करते हुए, भीष्म क्यूब्स (सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल) जैसे नवीनतम प्रयास की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मिशन संचालन समूह को पिछले कुछ वर्षों के दौरान एनएचएम के तहत हासिल की गई उपलब्धियों से अवगत कराया गया और विभिन्न मिशनों के लिए भविष्य के लक्ष्यों को चिह्नित किया गया। पहली बार,

प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को भी एमएसजी में शामिल किया गया। एनएचएम और पीएम-एबीएचआईएम की उपलब्धियों और भविष्य के लक्ष्यों पर प्रस्तुतियाँ भी दी गईं, जिसमें मिशन के तहत किए गए विकास, इसके घटकों और भविष्य के एजेंडे को शामिल किया गया।

बैठक में निम्नलिखित उपलब्धियों की जानकारी दी गई

भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) के तहत प्रति एक लाख जीवित जन्में बच्चों में मातृ मृत्यु दर 100 का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 1990 से 2020 के बीच भारत में एमएमआर में 83 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो वैश्विक एमएमआर गिरावट से कहीं ज़्यादा है।

इस अवधि के दौरान भारत में शिशु मृत्यु दर में 69 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जबकि वैश्विक शिशु मृत्यु दर में 55 प्रतिशत की गिरावट देखी गई

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 75 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक गिरावट दर 58 प्रतिशत है। एसआरएस 2020 के अनुसार, 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सतत विकास लक्ष्य हासिल कर लिया है

कुल प्रजनन दर 1992-93 में 3.4 से घटकर 2019-21 में 2.0 हो गई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5), 2019-21 के अनुसार 31 राज्यों ने प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर हासिल कर लिया है।

जेब से किया जाने वाला व्यय 2004-05 में कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) के 69.4 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में टीएचई का 39.4 प्रतिशत हो गया है, जबकि सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2004-05 में टीएफआर के 22.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में टीएचई का 48 प्रतिशत हो गया है।

एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य मानव संसाधन संवर्धन (एचआरएच) में वृद्धि, 2006-07 के 23 हजार से बढ़कर 2023-24 में 5.23 लाख हो गई।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15.05.2015 को भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन के लिए प्रमाणित किया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 8 अक्टूबर 2024 को, घोषणा की कि भारत सरकार ने ट्रैकोमा को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है

28 फरवरी 2025 तक , कुल संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में से 85 प्रतिशते में सेवाओं का विस्तारित पैकेज उपलब्ध है

आज देश में 1.76 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं

पिछले 5 वर्षों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आने वाले मरीजों की वार्षिक संख्या 2019-20 के 13.49 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 121.03 करोड़ हो गई है

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयोजित सत्रों की संख्या 2019-20 के 0.11 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1.54 करोड़ हो गई है।

एनसीडी स्क्रीनिंग की संख्या 2019-20 के 10.94 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 109.55 करोड़ हो गई

टेली-परामर्श की संख्या 2019-20 में 0.26 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 11.83 करोड़ हो गई

राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2015-23 के दौरान टीबी के मामलों में 18 प्रतिशत की कमी देखी गई, जो वैश्विक कमी से दोगुनी से भी अधिक है; जबकि मृत्यु दर में 21 प्रतिशत की कमी देखी गई।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा 748 जिलों को कवर किया गया है। इस योजना में 26.97 लाख रोगियों को कवर किया गया है तथा कुल 3.27 करोड़ सत्र आयोजित किए गए हैं।

28 फरवरी 2025 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 5 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 1.84 लाख रोगियों का निदान किया जा चुका है और 2.24 करोड़ सिकल सेल कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

मलेरिया उन्मूलन मिशन के तहत 2014 की तुलना में 2023 में मलेरिया के मामलों में 79.3 प्रतिशत की कमी देखी गई; जबकि मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की संख्या 2014 की तुलना में 2023 में 85.2 प्रतिशत कम हुई।

भारत ने 2023 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है, अर्थात ब्लॉक स्तर पर कालाजार के वार्षिक मामलों को घटाकर प्रति दस हजार की आबादी पर एक से भी कम करना है, जो सतत विकास लक्ष्य से अधिक है।

जून 2024 में स्वास्थ्य सुविधाओं के स्व-मूल्यांकन के लिए ओडीके टूल किट लॉन्च किया गया और कुल स्वास्थ्य सुविधाओं में से 95 प्रतिशत का मूल्यांकन किया जा चुका है

इस सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत हासिल की गई प्रगति और पिछले कुछ वर्षों में राज्यों को दिए गए समर्थन की सराहना की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देना शामिल है, जो टेली-परामर्श सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। देश में मोटापे की समस्या से निपटने के लिए आयुष समाधान के साथ-साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्क्रीनिंग और प्रबंधन पर जोर दिया गया।

बैठक में नीतिगत ढांचे, परिचालन नीतियों और वित्तीय मानदंडों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी करना और एनएचएम के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायसंगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, बाल और मातृ मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना और लिंग और जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखना है।

जेपी नड्डा ने कहा कि एमएसजी बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और जमीनी स्तर पर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक से प्राप्त लोगों की प्रतिक्रियाओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किए जाने वाले उपायों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

पृष्ठभूमि: मिशन संचालन समूह एनएचएम के तहत सर्वोच्च नीति-निर्माण और संचालन संस्था है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए व्यापक नीति निर्देश और शासन प्रदान करती है। एमएसजी राष्ट्र की स्वास्थ्य सेवा पहलों को संचालित करने वाली नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एनएचएम के तहत सभी योजनाओं और घटकों के लिए वित्तीय मानदंडों को मंजूरी देने के लिए पूरी तरह से सशक्त है और नीति निर्माण एवं संचालन में अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ईपीसी) को सलाह देता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत 2005 में अपनी स्थापना के बाद से, जिसे बाद में एनएचएम में शामिल कर लिया गया, एमएसजी ने एनएचएम के तहत 8 बैठकें और एनआरएचएम के तहत 9 बैठकें आयोजित की हैं। एमएसजी की अंतिम बैठक 11 जनवरी, 2023 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। इन बैठकों ने उल्लेखनीय रूप से देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों के संरेखण के लिए एक मंच प्रदान किया है।

मिशन संचालन समूह ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सेवा वितरण में सुधार करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने वाली पहलों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बैठक भारत में एक लचीली और उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण की दिशा में जारी प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

Jagran

गाजियाबाद में तीन मजदूरों की मौत मामले में NHRC सख्त, पुलिस से मांगा जवाब

Ghaziabad Crime राजनगर एक्सटेंशन में फरवरी में चार दिन में तीन कामगारों की निर्माणाधीन साइट पर हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पुलिस से जवाब तलब किया है। शिकायतकर्ता राजीव कुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने तीनों मामलों में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया और लापरवाही या गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज नहीं किया।

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/ghaziabad-ncr-nhrc-seeks-response-from-police-in-the-case-of-death-of-three-workers-in-rajnagar-extension-23894519.html

By vinit Edited By: Monu Kumar JhaUpdated: Tue, 04 Mar 2025 03:42 PM (IST)

HighLights

राजनगर एक्सटेंशन में बीते महीने निर्माणाधीन साइटों पर हुए हादसों में तीन कामगारों की मौत हो गई थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत, पुलिस पर आरोप शिकायत न मिलने पर खुद संज्ञान लेकर लापरवाही या गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज नहीं किया।

एनएचआरसी ने पुलिस को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। Ghaziabad Crime: राजनगर एक्सटेंशन में फरवरी में चार दिन में तीन कामगारों की निर्माणाधीन साइट पर हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से जवाब तलब किया है। शिकायतकर्ता राजीव कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तीनों मामलों में गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया।

पुलिस (Ghaziabad Police) ने शिकायत न मिलने पर खुद संज्ञान लेकर लापरवाही या गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज नहीं किया। एनएचआरसी ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है।

15 दिन में जांच रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने के मिले आदेश

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सोमवार को साहिबाबाद निवासी राजीव कुमार शर्मा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद पुलिस से फरवरी माह में राजनगर एक्सटेंशन में हुई तीन कामगारों की मौत के मामले में जांच करवा कर 15 दिन में जांच रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

राजीव कुमार शर्मा के मुताबिक तीनों ही मामलों में स्थानीय पुलिस ने बिल्डरों और ठेकेदारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के बजाय यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था कि मृतकों के स्वजन ने लिखित शिकायत नहीं दी है।

19 फरवरी को NHRC में दाखिल की थी जनहित याचिका

जबकि नियमानुसार अगर मृतकों के स्वजन की और से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी तब भी पुलिस को घटना पर स्वयं संज्ञान लेकर घटना के जिम्मेदार बिल्डरों और ठेकेदारों के विरुद्ध गैर इरादातन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी।

नाबालिग की मौत के मामले में श्रम कानून के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था। मानव अधिकार पक्षकार राजीव कुमार शर्मा ने 19 फरवरी को इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक जनहित याचिका दाखिल की थी।